an>

Title: Need to undertake developmental programmes in minority concentration districts in Maharashtra under Multi-Sectoral Development Programme.

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी)** ः केन्द्र सरकार के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का समावेश करने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विकास न होने की वजह से देश तथा राज्य के विकास में बाधाएँ आ रही हैं।

मेरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के भिवंडी शहर तथा परिसर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ लोग अपनी दिनचर्या बहुत ही कठिनाई और चिंताजनक स्थिति में बिता रहे हैं। केंद्र सरकार के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भिवंडी तथा महाराष्ट्र राज्य के नीचे दर्शाये गये जिलों के अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का समावेश करने की मांग राज्य सरकार तथा अल्पसंख्यक जनता से हो रही है। जिन जिलों और अल्पसंख्यक क्षेत्रों का बहुउद्देशीय कार्यक्रम अंतर्गत समावेश करना है, उन जिलों के नाम हैः- 1. (ठाणे) तहसील-भिवंडी, मुंब्रा, मिरा भाईदर, 2. (नाशिक) तहसील- नाशिक, मालेगांव, 3. (सांगली) तहसील- मिरज, 4. (जलगांव) तहसील जलगांव, भुसावल, बोधवल, 5. (बुलढाणा) तहसील- मलकापुर, 6. (अकोला) तहसील- अकोला, 7. (धुले) तहसील-धुले, 8. (अमरावती) तहसील- अमरावती, 9. (औरंगाबाद) तहसील-औरंगाबाद।

इन जिलों के अल्पसंख्यक क्षेत्रों का समावेश इस योजना में होने से अल्पसंख्यक क्षेत्रों का भौतिक व सामाजिक विकास तेजी से होगा। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत इन सब क्षेत्रों के शिक्षा, रोज़गार, व्यापार, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा खेल मैदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निधि की उपलब्धता होगी।

अतः मैं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय से नम्र निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त सूची के अल्पसंख्यक क्षेत्रों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता से समावेश करने की कृपा करें।